

बाल-ववाह समाप्त करने की दशा में प्रगति

प्रलिस के लयः

सतत वकस लकष्य 5.3, UNICEF, बाल-ववाह परतषध अधनलयम, 2006, बाल ववाह नषध अधकलरल, धनलकषुमी योजना

मेनुस के लयः

बाल ववाह से संबंघतल परुख कारक, वधलयी ढाँचा और भारत में बाल ववाह की रोकथाम से संबंघतल पहल

सुरतः इकनॉमकल टाइडस

चरुा में कुरुुँ?

'द लैसेट ग्लुबल हेल्थ' जरुनल में परकाशतल एक हालयल अधययन भारत में बाल-ववाह की ढुजूदा स्थतलतल कु उजागर करता है, जसलसे सडलज में गहनता से वयाप्त इस कुप्रथा के खलललफ लडुई में परगतल तलथा वकललता दुनुुँ का पता चलता है ।

अधययन में उजागर परुख रुडुनलन कुरुा हैं?

■ भारत में स्थतलतल:

- वरुष 1993 में बाल-ववाह के डलडले 49% थे कु वरुष 2021 में घटकर 22% हु गए । बालकुुँ के बाल-ववाह के डलडले वरुष 2006 में 7% थे कु वरुष 2021 में घटकर 2% हु गए, यह राष्ट्रलय सतर पर सडगर गरलवट का संकेत देता है ।
 - हालुुक वरुष 2016 से 2021 के डलडल यह परगतल धलडुी हु गई तलथा कुडु राजुुँ में बाल-ववाह में चतलजनक वृदुध हुई ।
 - वशलष रूड से डुह राजुुँ में बालकल बाल-ववाह में वृदुध देखल गई, जनलडें डणगुरल, पंजाब, तरगुरल तलथा पशुचडल डंगलल शलडलल हैं ।
 - डतुतुलसगदु, गुवल, डणगुरल तलथा पंजाब सहलतल आठ राजुुँ में बालकुुँ के बाल-ववाह में वृदुध देखल गई ।
- वैशुवकल रुडुनलन: वशलष सतर पर बाल-ववाह के वरुदुध हुई परगतल उलुलेखनलय रही है कतु कुवडु-19 डलडलरल ने इस परगतल कु खतरे में डलल दलल, जसलसे एक दशक में लडडग 10 डललयन से अधकल बालकललुुँ के बाल-ववाह का खतरा डदु गलल है ।

बाल-ववाह से संबंघतल परुख कारक कुरुा हैं?

- आरुथकल कारक: गरुडुी में कुवनयापन करने वलले परवलर ववाह कु लडुकी की जडुडेदलरल कु उसके पतलके परवलर कु हसुतलंतरतल करके अपने आरुथकल डुडु कु डड करने के सलधन के रूड में देख सकते हैं ।
 - कुडु कुषेतुरुुँ में दहेज देने की परंपरल परवलरुुँ कु डेटी के उचतल आयु डूरुण हुने परसुचु दहेज ललगत से डचने के लयल डड उडुर में डेटललुुँ का ववाह करने के लयल परडलवतल कर सकतुी है ।
 - इसके अतरलकलत परलकुतुकल आपदललुुँ अथवल कुषल संकट से गरसुत कुषेतुरुुँ में आरुथकल कठनलडुुँ का सलडनल करने वलले परवलर इस सडसुुल का सलडनल करने अथवल सुनशलुुतल करने के लयल शीघुर ववाह का वकललुु चुन सकते हैं ।
- सलडलजकल डलनदंड और डलरंपरकल डुरथलरुुँ: लंडे सडड से चली आ रहे रलत-रलवललुुँ और परंपरलरुुँ अकसुर एकसलडलजकल आदरुश के रूड में डड उडुर में ववाह कु डुरलथडकलतल देतुी है, कु डुडुडुुँ तक इस डुरथल कु कलयड रखता है ।
 - सडुदलय यल परवलर की ओर से डुरचलतल रलत-रलवललुुँ और परंपरलरुुँ के अनुरूड दडलव डललने के कारण वशलषकर लडुकललुुँ का ववाह जलदुी हु जाता है ।
- लैगकल असडनलनल एवं डेदडलव: लडकुुँ की तुलनल में लडकुुँ की डडु हुने की कुषडतल डड उडुर में ववाह में डहततुवडूरुण युगदलन देतुी है ।
 - कु परवलर डड उडुर में शलदुी कु अपनी डेटललुुँ के डवषलड कु सुरकुषतल करने के सलधन के रूड में देखते हैं , वे अकसुर अपनी डेटललुुँ के लयल शकलषल और कुरुरलडर में उनुनतल के डलरंपरकल तरुीकुुँ की डकलय इसे चुनते हैं ।

नुुटः

यूनिसिफ बाल विवाह को लड़कियों और लड़कों दोनों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में वर्गीकृत करता है।

- **सतत विकास लक्ष्य** 5.3 में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक लैंगिक समानता और महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तीकरण के लक्ष्य के साथ सतत विकास लक्ष्य 5 को प्राप्त करने में बाल विवाह उन्मूलन महत्त्वपूर्ण है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्ष 2022 में दुनिया भर में 5 में से 1 लड़की (19%) की शादी बचपन में ही कर दी गई।

भारत में बाल विवाह से संबंधित वधायी ढाँचा और पहल क्या हैं?

- **वैधानिक ढाँचा:** भारत ने 2006 में **बाल विवाह नषिध अधिनियम** लागू किया, जिसमें पुरुषों के लिये विवाह की कानूनी उम्र 21 वर्ष और महिलाओं के लिये 18 वर्ष निर्धारित की गई।
 - बाल विवाह नषिध अधिनियम की धारा 16 राज्य सरकारों को वशिष्ट कर्षेत्रों के लिये 'बाल विवाह नषिध अधिकारी (CMPO)' नियुक्त करने की अनुमति देती है।
 - CMPO बाल विवाह को रोकने, अभियोजन के लिये साक्ष्य एकत्र करने, ऐसे विवाहों को बढ़ावा देने या सहायता के खिलाफ परामर्श देने, उनके हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समुदायों को संवेदनशील बनाने के लिये ज़िम्मेदार है।
 - सरकार ने महिलाओं की शादी की उम्र को पुरुषों के बराबर करने के लिये इसे 21 साल करने के लिये 'बाल विवाह नषिध (संशोधन) वधियक, 2021' नाम से एक वधियक पेश किया है।
- **संबंधित पहल:**
 - धनलक्ष्मी योजना: यह बीमा कवरेज वाली बालिका के लिये एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।
 - इसका उद्देश्य माता-पिता को चिकित्सा खर्चों के लिये बीमा कवरेज की पेशकश और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित कर बाल विवाह प्रथा को खत्म करना है।
 - **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)** जैसी योजनाओं का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना एवं बाल विवाह को हतोत्साहित करना है।

नोट:

ओडिशा सरकार ने बाल विवाह से निपटने के लिये एक व्यापक रणनीति तैयार की है। इसमें लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति और गाँव में उपस्थिति पर नज़र रखी जाती है तथा 10-19 वर्ष की लड़कियों के लिये "अद्विका" मंच का प्रयोग किया जाता है।

- कमज़ोर जनजातीय समूहों को प्रोत्साहन के साथ गाँवों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने के लिये दशिया-नरिदेश मौजूद हैं।
- ज़िले विभिन्न दृष्टिकोण लागू करते हैं, जैसे- लड़कियों का डेटाबेस बनाए रखना और **विवाह में आधार संख्या** अनिवार्य करना।

आगे की राह

- **आर्थिक सशक्तीकरण पहल:** जोखिमपूर्ण स्थिति वाली लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना, शीघ्र विवाह के लिये व्यवहार्य विकल्प प्रदान करना चाहिये।
 - परिवारों के लिये सूक्ष्म ऋण तक पहुँच को सुवर्धित बनाने, आय सृजन को प्रोत्साहित करने और कम उम्र में विवाह के लिये वित्तीय दबाव को कम करने की आवश्यकता है।
- **कला और मीडिया के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव:** बाल विवाह के परिणामों को लेकर जागरूक करने और शक्ति करने के लिये कला-आधारित कार्यशालाएँ, थिएटर प्रदर्शन या सामुदायिक कथा सत्र आयोजित करने की आवश्यकता है।
 - संगीत, नुककड़ नाटक या लघु फिलिमों के माध्यम से प्रभावी ढंग से अभियानों के संचालन के लिये स्थानीय कलाकारों और प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है।
- **सहकर्मी शिक्षा और परामर्श कार्यक्रम:** युवा नेताओं को बाल विवाह के वरिद्ध कालत करने के लिये प्रशिक्षित करने, उन्हें अपने समुदायों के भीतर साथियों को शक्ति करने और सलाह देने हेतु सशक्त करने की आवश्यकता है।
 - स्कूलों में व्यापक शिक्षा मॉड्यूल पेश करने, छात्रों के बीच चर्चा और जागरूकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

2016-2017:

प्रश्न. राष्ट्रीय बाल नीतिके मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिये तथा इसके कार्यान्वयन की स्थितिकी वविचना कीजिये। (2016)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/progress-in-ending-child-marriage>

